

संख्या - 345/V-2011-34(आ0)/2008

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा

- 1- उपाध्यक्ष,  
मिसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण  
देहरादून/हरिद्वार।  
3- सचिव,  
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण  
देहरादून/हरिद्वार/गंगोत्री।

- 2- समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।  
4- नियत प्राधिकारी,  
विनियमित क्षेत्र,  
उत्तराखण्ड।

आवास अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 27 मार्च, 2012

विषय: भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 के निर्गत होने से पूर्व लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2009-V-2011-55(आ0)/2006टी0सी0, शासनादेश संख्या-2010-V-2011-55(आ0)/2006टी0सी, शासनादेश संख्या-2012-V-2011-55(आ0)/2006 टी0सी0, एवं अधिसूचना संख्या-2011-V-2011-55(आ0)/2006 टी0सी0 समदिनांकित 17-11-2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र में भवन मानचित्र एवं परियोजनाओं के स्वीकृति हेतु विचाराधीन प्रकरण, जो उक्त उपविधि/विनियम-2011 के प्रवृत्त होने के पूर्व से प्राधिकरणों में लम्बित है, का निस्तारण पूर्व में प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों/विनियमों के अनुसार ही किया जाये, किन्तु उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत मामलों के सम्बन्ध में उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक 17-11-2011 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

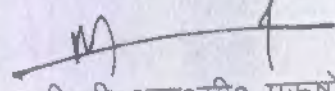
(पी0सी0 शर्मा)  
प्रमुख सचिव



संख्या - 345 (1)/V-2012-तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
1. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, देहरादून/हरिद्वार।
  2. अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
  3. वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
  4. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
  5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

  
(डा0बी0वी0आर0सी0 पुरुषोत्तम  
अपर सचिव